

राजस्थान सरकार
राजस्व § गृ.प.६ § विभाग

प्रेषित:- §1§ समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
§2§ समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।

क्रमांक:- प.६§19§राज-६/११/४

जयपुर, दिनांक:-13-4-2000

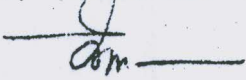
-: परिपत्र :-

विषय:- आबादी हेतु भूमियों का नियमन बावद ।


विभागीय परिपत्र क्रमांक प.६§10§राज-४/११ दिनांक 23.4.77 द्वारा
ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचायक, चारागाह, वनभूमि, गैर भुमीकन तथा आबादी भूमि
पर 1.7.75 तक आवास गृह या बाड़े बनाकर किये गये सभी अतिक्रमणों को
नियमन करने के आदेश दिये गये थे ।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 202/95 टी० एन०
गोडावरमन तिलकपड बनाम यू०ओ०आर० एण्ड अदरस में पारित निर्णय दिनांक
दिनांक 12.12.96 में यह स्पष्ट किया गया है कि केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम
में निहित भूमि का अन्य उपयोग अधिनियम एवं नियम में निर्धारित प्रक्रिया के
अपनाये के पश्चात ही किया जा सकता है । नियमन के लिए भी उक्त प्रावधानों
की पालना आवश्यक है ।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में स्पष्ट किया जाता है कि परिपत्र
दिनांक 23.4.77 में निहित वन भूमि पर वन उपयोग में आ रही भूमि का
अन्य उपयोग या नियमन केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की प्रक्रिया की
पालना करते हुए ही किया जावे अन्यथा ऐसी भूमियों का नियमन नहीं किया
जावे ।


§ शिव कुमार शर्मा §
शासन उप सचिव

प. तिथिपि: १० निबन्ध, राजस्व गृह व राजस्थान, अजमेर ।


शासन उप सचिव 13/4/2000

मनोज